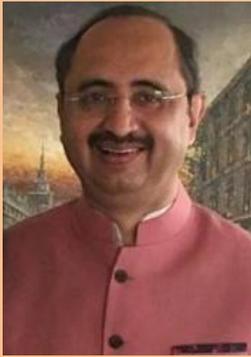


# M.C.Ptk e – NEWS

*MUNICIPAL CORPORATION PATHANKOT*



**Sh. Anil Vasudeva  
(Mayor)**

**March 2017**



**Sh. Surinder Singh  
PCS (Commissioner)**

Municipal Corporation Pathankot is releasing its e-newsletter for March 2017, which has been named as MCPtk e-News. E-News will bring awareness among citizens about various works done and being taken up by MC Pathankot. The newsletter will act like a common platform for public and MC Pathankot, with this effort we will be closer to the citizens by focusing on development activities of MC Pathankot. We congratulate the whole team for this noble concept and also wish continuity of publication of this newsletter.

## **ATAL MISSION FOR REJUVENATION AND URBAN TRANSFORMATION (AMRUT)**

AMRUT Mission was launched by ministry of Urban Development Government of India on 25 June, 2015.

### **Objectives:-**

Providing basic services (e.g Water supply, Sewerage, Parks and Urban transportation) to households and build amenities in cities which will improve the quality of life for all, especially the poor and the disadvantaged is a national priority of this scheme.

**Government of Punjab in the department of Local Government has taken various initiatives to achieve these reforms.**

- Preparation of GIS based master plans.
- Digital India initiatives for laying cables for digital/ web networking.
- Transfer of funds under 14<sup>th</sup> Finance Commission to ULBs.
- Solar roof top panels policy and Net Metering, for more details click to the website of PEDDA : [solarpunjab.com](http://solarpunjab.com)
- Rain Water Harvesting (RWH) : Already there is a provision in Punjab Municipal Building Bye Laws for RWH, for more details please visit website of Department of Local Government Punjab : [lgpunjab.gov.in](http://lgpunjab.gov.in)
- To achieve full potential of advertisement revenue by making policy for destination specific potential having dynamic pricing module, Advertisement policy was notified by the Government which is available online.

- Incentives to Green buildings : A policy was notified by the Government giving incentives to green buildings, for more details visit at the website of MC Pathankot : [www.mcpathankot.gov.in](http://www.mcpathankot.gov.in)
- Cadre linked training: The Government has initiated various cadre linked training programs under AMRUT and other schemes.
- Complete the credit ratings of the ULBs : Government has engaged a company called M/s Brickwork Ratings India Pvt. Ltd.
- SLIP and SAAP have been prepared and action plan has been also prepared for water supply, sewerage and action plan for parks and open spaces in under process.

### **SWACHH BHARAT MISSION (SBM)**

The Swachh Bharat Mission (SBM) emanates from the vision of the government articulated in the address of the President of India in his address to the joint session of Parliament on 9<sup>th</sup> June 2014 :-

" We must not tolerate the indignity of homes without toilets and public places littered with garbage, for ensuring hygiene, waste management and sanitation across the nation, a " Swachh Bharat Mission" will be launched. This will be tribute to Mahatma Gandhi on his 150<sup>th</sup> birthday anniversary to be celebrated in the year 2019."

SBM is being implemented by the ministry of Urban Development (M/o UD) and by the ministry of Drinking water and sanitation (M/o DWS) for urban and rural areas respectively. These guidelines are for the implementation of Swachh Bharat Mission (Urban).

**Mission Objectives:-**

- Elimination of open defecation.
- Eradication of manual scavenging.
- Modern and scientific municipal solid waste management.
- To effect behavioral change regarding healthy sanitation practices.
- Generate awareness about sanitation and its linkage with public health.
- Capacity Augmentation for ULBs.
- To create an enabling environment for private sector participation in Capex (Capital expenditure) and Opex (Operation and maintenance).

**Mission Components:-**

- Household toilets, including conversion of insanitary latrines into pour flush latrines.
- Community toilets.
- Public toilets.
- Solid waste management.
- IEC and public awareness.
- Capacity building and Administration and office expenses (A & OE).

# Municipal Corporation Pathankot

## Swachh Bharat Mission

- Efforts done by municipal corporation pathankot to make city clean under Swachh Bharat Mission.

**नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत एक्शन**

### अब कचरा जलाने पर भी चालान, कम से कम 5 हजार जुर्माना वूसलेगा निगम

पठानकोट | ओपन डंप पर कचरा फैकने पर चालान के बाद अब कचरा जलाने पर भी निगम की टीम चालान काटेगी। कम से कम जुर्माना फीस 5 हजार रुपए रखा गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नोटिफिकेशन मिलने के बाद निगम की एक्शन लेने की योजना है। निगम ने 3 दिन में 2 लोगों के चालान काटे हैं। इसकी पुष्टि हेल्थ अफसर डॉ. एनके सिंह ने की है। इसके अलावा शहर की सड़कों/गलियों और खाली प्लॉटों में गिरने वाले कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन (सीएंडडी) वेस्ट से आम पब्लिक को राहत देने को नगर निगम ने सरकार द्वारा इसी साल बनाए कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्ट को शहर में लागू किया है। शहर के 50 वार्डों की सड़कों और गलियों में अगर कोई अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन एडिशनस, अल्ट्रेशन, डेमोलिशन व कंस्ट्रक्शन साइट पर रेत, बजरी, ईटे, सरिया व अन्य कंस्ट्रक्शन मेटीरियल रखने पर 2500 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इसमें 2 हजार रुपए लिफ्टिंग व 500 रुपए जुर्माना होगा।

# Municipal Corporation Pathankot

## Property Tax Payments

### एक अप्रैल से 38% जुमाने के साथ भरनी होगी रिटर्न

27 हजार में से 10 फीसदी ने ही जमा करवाया प्रॉपर्टी टैक्स, 17 नए गांवों में भी 31 मार्च के बाद लगेगा टैक्स

शहर वाइड | नगरपालिका

प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए 6 दिन बचे हैं और 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 20 फीसदी जुर्माने और 18 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। बता दें कि

शहर के 27 हजार प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए 2016-17 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया है। हालांकि, लोगों का सहयोग करने के लिए नगर निगम ने सुझाव देने में भी अधिकार खूब रखा है। वहीं 17 नए गांवों ने

प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जिसमें निगम ने 2.26 लाख रुपये का बकाया दे, पुराने शहर (नए 17 गांवों को छोड़) में कुल 45114 प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 27 हजार केवल रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं। इनमें से 2637 ने ही टैक्स जमा कराया है।

#### 14 इंडस्ट्री मालिकों का भी टैक्स पहिना

नगर निगम ने 6000 कार्पोरेशन में से 5850 उपभोक्ताओं और 14 इंडस्ट्रीज में से 1000 को भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया। विरलक्षण नगर निगम अधिनियम 31 मार्च तक अपने 2.75 करोड़ के टारगेट को अपीत करने के लिए कोअपरेटिव बकाये में लगे हैं। 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाएगा। कई बिजनेस और इंडस्ट्री के साथ टैक्स देना होगा।

### छुट्टियों में भी जमा हो सकेगा प्रॉपर्टी टैक्स

पठानकोट | प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए नगर निगम का ऑफिस छुट्टियों में भी खुला रहेगा। निगम कमिश्नर सुरिंद्र सिंह ने बताया कि 31 मार्च से पहले टैक्स जमा करवाने पर 20 प्रतिशत जुर्माने व 18 प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी। जिन्होंने साल 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 का टैक्स जमा नहीं कराया, वे बनता टैक्स निगम कार्यालय में जमा करवाएं।

### हाउस टैक्स एरियर के डिफाल्टर्स की प्रॉपर्टी आज से सीज करेगा निगम

पठानकोट | प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स एरियर जमा न करवाने वाले डिफाल्टर्स पर कार्रवाई की योजना निगम ने तैयार कर ली है। निगम ने 10 हजार से 1.5 लाख तक के बकाया राशि वाले 200 डिफाल्टर्स की लिस्ट बनाई, जिन 6पर बुधवार से एक्शन होगा। सुपरिंटेंडेंट जनरल राहुल शर्मा ने

बताया कि 2016-17 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 31 मार्च के बाद 20 फीसदी जुर्माना वसूल किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि शहर में 60 हजार प्रॉपर्टी रजिस्टर है, जिनमें से 30 हजार प्रॉपर्टी टैक्सबल है। 2016-17 में 2.5 करोड़ का टारगेट था, जिसमें 2.30 करोड़ वसूल लिए हैं।

# Municipal Corporation Pathankot

## Water Supply & Sewer Charges

- Action taken by Municipal Corporation against illegal connections of water supply & sewer in the city

### लमीनी में वाटर सप्लाई के 76 अवैध कनेक्शन मिले, पांच साल का बिल भरने पर होंगे रेगुलर

सर्वे टीम इंचार्ज अश्विनी शर्मा बोले-प्लाटों में झुगियां किराए पर देने वालों की भी बनाई डिटेल्स, नोटिस जारी होंगे

नगर निगम की वाटर सप्लाई एंड सेनिटेशन ब्रांच की सर्वे टीम ने लमीनी एरिया में 76 अवैध कनेक्शनों को पकड़ने का काम किया है। इनमें इंफ़ॉर्मेट ट्रस्ट की 0.46 एकड़ स्कैम फे प्लॉट होल्डर भी शामिल हैं। सर्वे टीम में इंचार्ज अश्विनी शर्मा व इन्स्पेक्टर कमल शर्मा ने बताया कि 0.46 एकड़ स्कैम लमीनी में बने सभी मकान मालिकों को पिछले 11 साल से पानी और सेंटिनेज की सुविधा नगर निगम की ओर से दी जा रही है, लेकिन आज तक किसी प्लॉट या मकान मालिक ने मकान बनवाने से लेकर

एक भी बिल जमा नहीं कराया। अश्विनी शर्मा ने बताया कि उक्त स्कैम के रहत बने मकान मालिकों को जानकारी न होने के चलते उन्हें सुर्माया नहीं देना जाया, लेकिन 2005 से अब तक का बिल उन्हें जमा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उक्त मकान की रजिस्ट्री चार की है तो वह उसी समय से अब तक का बिल दे सकता है। शर्मा ने बताया कि उक्त एरिया में कुछ प्लॉट मालिक प्लाटों का कम्प्लायर चूक कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई टेमाग निगम को नहीं दिया जा रहा, प्लाटों में झुगियां बनाकर किराए पर दे रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट बनना ही यह है, इसे जल्द नोटिस जारी किए जाएंगे।

### गर्मी के मौसम से पहले टीम ने भरे पानी के सैंपल

सुबानपुर: तेजा प्रियान की ओर से गर्मी के मौसम को ठंडा करने के लिए हुए पानी की नमूना लेने के लिए तुलसी पार्क। इन्होंने तहत मंत्रालय को तहत प्रियान की टीम की ओर से पानी के सैंपल लेने शुरू किए गए। इन्स्पेक्टर अश्विनी शर्मा ने बताया कि उक्त टीम को और से रिपोर्ट अलावा सुबानपुर और लक्ष्मी गार्डन के प्लॉट से पानी के सैंपल लिए गए। इन सैंपल

को चंडीगढ़ में जांच के लिए भेजा जाएगा। इतकी रिपोर्ट के आकर पर अगली कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार शर्मा के अन्य क्षेत्रों से भी सैंपल लिए जाएंगे। इन सैंपल का उद्देश्य इन क्षेत्रों में मुश्किल जल की गुणवत्ता की जांच करना है। इस सैंपल पर इन्स्पेक्टर सुधीर अग्नि, रवींद्र कुमार, प्रियान शर्मा, राज शर्मा, अरुण बटौरा और रमेश कुमार मौजूद थे।

बूथ अलाउमेंट में पुरानों को तरजीह, 10 तक करें अवैध प्लॉट्स। बिल प्रोसेसिंग कार्यालय में पिछले सालों के लिए बिल अर्बिट और एस्टिमेट बनाने में बिल बनाने वाले को प्रोसेसिंग की जाएगी। बिल अलाउमेंट के लिए 10 वर्षों को बिल 5 बने तक एस्टिमेटेशन जमा करना अनिवार्य है। इतकी जानकारी प्रोसेसिंग अधिकारियों के सह बैठक के बाद दीली। अतिरिक्त सुधीर अग्नि ने बताया कि इनके तहत 5 एस्टिमेट कार्यालय के पुराने बिल पर रहे कंप्यूटर, फोटो स्टेट, क्लैक, रोल फोरो को प्रोसेसिंग की जाएगी।

### बिल न भरने पर लक्ष्मी गार्डन कालोनी में पानी के 5 अवैध कनेक्शन काटे

एक हफ्ते में बिल न भरा तो पेंडिंग कनेक्शन भी काटेंगे : कनिष्ठ अभियंता

जल सप्लाई एंड सेनिटेशन विभाग की ओर से उपभोक्ताओं से पानी के बिलों के बकाया की वसूली के लिए अभियान छेड़ दिया है। जेई नीतिन धोमान ने बताया कि विभाग की ओर से जलयोजना लक्ष्मी गार्डन कालोनी नजदीक आईटीआई में चेकिंग की गई। जिसमें पांच उपभोक्ताओं के प्रोड्युस कनेक्शन बिल बकाया न देने के कारण काट दिए गए। वहीं, चार पब्लिक स्टैंड पोस्ट कनेक्शन को पानी के दुरुपयोग के कारण बंद किया गया। उन्होंने बताया कि यहां



लक्ष्मी गार्डन कालोनी में कनेक्शन काटते विभाग के कर्मचारी।

पर लगभग 700 पानी के कनेक्शन हैं तथा दस लाख रुपये के करीब पानी के बिल बकाया हैं। इनकी वसूली के लिए उपभोक्ताओं को नोटिस दिए जा चुके हैं। अगर एक

सप्ताह के भीतर बिल जमा न हुए तो इनके बकाये हैं, उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस मौके पर बकाया को आर्डीनेटर भूपिन्द्र सिंह, गौसपाल, कमल देव, अमी चंद मौजूद थे।



**Contact us:-**

***Municipal Corporation Pathankot***

***Opp. Shimla Park***

***Main Bazar, Pathankot***

***e-mail :- eomcptk@yahoo.co.in***

***Tel.:- 01862220230***